आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 22.08.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- देहरादून जिले में ग्रामीण महिलाओं की हस्तनिर्मित राखियों की बढ़ी मांग। नारी सशक्तीकरण और स्थानीय स्वरोजगार को मिल रही मजबूती।
- देहरादून–मसूरी मार्ग पर पानीवाला बैंड के पास भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। धारचूला–तवाघाट मार्ग पर यातायात सुचारू।

भारत–नेपाल बैठक

भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन व सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में सीमा पार से होने वाले अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेष रूप से एकीकृत जांच चौकियों, सड़कों और रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने तथा इनके प्रभावी उपयोग पर विचार–विमर्श किया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और सीमा स्तंभों के रख–रखाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत समन्वय और क्षमता विकास को मजबूत करने के उपायों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े मामलों में नियमित संपर्क और समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में निरंतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक नेपाल में आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक हुई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को

बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन के लिए गांवों में रोजगार के साथ बेहतर आजीविका, सुविधाएं और संभावनाएं विकसित करना जरूरी है। उन्होंने बैठक में मिले सुझावों के आधार पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने और विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार और आजीविका योजनाओं की जानकारी गांव स्तर तक सरलता से पहुंचाई जाए और लाभ लेने की प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाए। उन्होंने स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़ने तथा स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया।

विशेष गहन पुनरीक्षण

देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 11 लाख 90 हजार से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 2003 की मतदाता सूची से संबंधित विसंगतियों के चलते 5 लाख 47 हजार 617 लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 3 लाख 95 हजार से अधिक की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि दावे–आपत्तियों के निस्तारण में सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से बीएलए के माध्यम से मतदाताओं को सुनवाई प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील की।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल

प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण–एसआईआर को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। अधिक दावे–आपत्तियां प्राप्त होने वाले जिलों में निगरानी के लिए नौ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलायुक्तों को मतदाता सूची के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही, सभी जिलों को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं।

महिला समूह/राखी

रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही देहरादून जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की हस्तनिर्मित राखियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकासखंडों की महिलाएं राखी को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। रायपुर विकासखंड के मालदेवता क्षेत्र की सास–बहू लीला रावत और अलका रावत

ने इस वर्ष दो हजार से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें करीब डेढ़ हजार राखियां तैयार हो चुकी हैं। पिछले वर्ष उन्होंने 12 सौ राखियां बेचकर करीब 25 हजार रुपये का मुनाफा कमाया था। इस बार उन्हें स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी ऑर्डर मिल रहे हैं।

वहीं, सहसपुर और डोईवाला की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब सौ महिलाएं भी विभिन्न डिजाइनों की राखियां तैयार कर बाजार में बेच रही हैं। सहायक परियोजना निदेशक अनीता पंवार ने बताया कि महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए 24 से 27 अगस्त तक उत्तराखंड सचिवालय में पांच स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून के प्रमुख मॉल में भी राखियों के स्टॉल लगाए जाने की तैयारी है।

देहरादून–मसूरी मार्ग

देहरादून–मसूरी मार्ग पर बारिश के कारण पानीवाला बैंड के पास सड़क की पूर्व निर्मित सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दी गई है। संबंधित विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम किया जा रहा है। प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यात्रियों से अत्यधिक बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और यात्रा से पहले मार्ग और मौसम की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। उधर, पिथौरागढ़ जिले में धारचूला–तवाघाट मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त कुलागाड़ पुल के स्थान पर वैकल्पिक पुल तैयार कर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। गौरतलब है कि 19 अगस्त को बोल्डर गिरने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था।

भारतीय मानक ब्यूरो

हरिद्वार के सिडकुल में भारतीय मानक ब्यूरो– बीआईएस, देहरादून शाखा कार्यालय ने औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य उद्योग जगत को पैकेजिंग और कॉस्मेटिक्स से संबंधित भारतीय मानकों की जानकारी देना और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। बीआईएस देहरादून के निदेशक व प्रमुख हेमंत बी. अडे ने कहा कि भारतीय मानक गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने उद्योगों से बीआईएस मानकों को अपनाकर, उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की अपील की। इस अवसर पर बीआईएस की संयुक्त निदेशक नीलम सिंह ने मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन प्रणाली की जानकारी दी। कार्यक्रम में सिडकुल क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।